



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5]

नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 2, 2012/पौष 12, 1933

No. 5]

NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 2, 2012/PAUSA 12, 1933

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 जनवरी, 2012

(आय-कर)

का.आ. 5(अ).—केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35कघ की उपधारा (8) के खंड (ग) के उपखंड (vii) के साथ पठित धारा 295 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (पहला संशोधन) नियम, 2011 है।

(2) ये उनके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. आय-कर नियम, 1962 के भाग 2 के उपभाग च च में, नियम 11-0 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

” धारा 35कघ के अधीन विनिर्दिष्ट कारबार के रूप में साध्य गृह परियोजना की अधिसूचना के लिए दिशानिर्देश ।

11-0क.(1) अधिनियम की धारा 35कघ की उपधारा (8) के खंड (ग) के उपखंड (vii) के अधीन विनिर्दिष्ट कारबार के रूप में साध्य गृह परियोजना के संबंध में अधिसूचना का प्ररूप और रीति निम्नानुसार होगी :—

(क) आवेदक परियोजना की अधिसूचना के लिए प्ररूप 3गढ़ में सदस्य (आईटी), केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली को आवेदन करेगा ;

(ख) यदि प्ररूप 3गढ़ में आवेदन में कोई त्रुटि पाई जाती है या उसके साथ सुसंगत दस्तावेज उपाबद्ध नहीं किए जाते हैं, आवेदक को कमी के पत्र की तामील की जाएगी ;

(ग) आवेदक कमी के पत्र की तामील की तारीख से पंद्रह दिनों की अवधि के भीतर या ऐसी और अवधि के भीतर जिसका इस निमित्त किए गए आवेदन पर विस्तार किया जाए, कमियों को दूर करेगा ;

(घ) यदि आवेदक इस प्रकार अनुज्ञात अवधि के भीतर कमी को दूर करने में असफल रहता है, तो बोर्ड यह समाधान हो जाने पर आवेदन को अवैध मानने के लिए कोई आदेश पारित कर सकेगा ;

(ङ) बोर्ड अनुमोदन प्रदान करने से पूर्व आवेदक से ऐसे दस्तावेजों या सूचना की मांग कर सकेगा जो वह उचित समझे और वह आवेदक के साथ-साथ आय-कर प्राधिकारियों और अन्य विभागों या अभिकरणों से और व्यौरे या सूचना मांग सकेगा जैसा कि वह उचित समझे ;

(च) बोर्ड राजपत्र में प्रकाशन के लिए परियोजना का अनुमोदन प्रदान करने के लिए या कारणों को लेखबद्ध करते हुए आवेदन को अस्वीकार करने की अधिसूचना जारी कर सकेगा ;

(छ) बोर्ड आवेदन को प्रत्याहृत कर सकेगा यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि निर्धारिती ने विनिर्दिष्ट कारबार से संबंधित क्रियाकलाप बंद कर दिए हैं या उसके क्रियाकलाप वास्तविक नहीं हैं या इस नियम के अधीन सभी या किन्हीं शर्तों के अधीन नहीं चलाए जा रहे हैं ;

(ज) किसी आवेदन को अविधिमान्य मानने का या आवेदन को अस्वीकार करने का या आवेदन को प्रत्याहृत करने या अधिसूचना को रद्द करने का कोई आदेश निर्धारिती को सुने जाने का अवसर दिए बिना पारित नहीं किया जाएगा ;

(झ) आवेदन को अविधिमान्य करने या अस्वीकार करने या अनुमोदन के प्रतिसंहरण करने के आदेश की प्रति आवेदक के साथ-साथ निर्धारण अधिकारी और निर्धारिती पर अधिकारिता रखने वाले आयुक्त को भेजी जाएगी ।

(2) किसी परियोजना पर अधिसूचना के लिए विचार किया जाएगा यदि वह निम्नलिखित शर्तों को पूरा करती है, अर्थात् :-

(क) आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा विरचित भागीदारी में साध्य गृह स्कीम के अधीन सशक्त सक्षम प्राधिकारी द्वारा परियोजना को पूर्व अनुमति प्राप्त होगी ;

(ख) परियोजना के प्रचालनों के प्रारंभ की तारीख 1 अप्रैल, 2011 को या उसके पश्चात् होगी ;

(ग) परियोजना भूमि के ऐसे टुकड़े पर होगी जिसका न्यूनतम क्षेत्र एक एकड़ होगा ;

(घ) परियोजना का कम-से-कम तीस प्रतिशत आबंटनीय किराया योग्य क्षेत्र आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के प्रवर्ग की साध्य गृह इकाइयों से बना होगा ;

(ङ) परियोजना का कम-से-कम साठ प्रतिशत आबंटनीय किराया योग्य क्षेत्र आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और निम्न आय वर्ग के प्रवर्ग की साध्य गृह इकाइयों से बना होगा ;

(च) परियोजना का कम-से-कम नब्बे प्रतिशत आबंटनीय किराया योग्य क्षेत्र आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, निम्न आय वर्ग और मध्य आय वर्ग के प्रवर्ग की साध्य गृह इकाइयों से बना होगा ;

(छ) परियोजना का शेष दस प्रतिशत या कम आबंटनीय किराया योग्य क्षेत्र आवासीय या वाणिज्यिक इकाइयों से बना होगा ;

(ज) विकसित और निर्मित की जाने वाली परियोजना का विन्यास और विशिष्टियां, जिसमें डिजाइन भी है, का अनुमोदन राज्य या संघ राज्यक्षेत्र की सरकार या उसके अधिकारित कार्यान्वयन अभिकरण द्वारा किया जाएगा ;

(झ) आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा विरचित भागीदारी में साध्य गृह स्कीम के अधीन सशक्त सक्षम प्राधिकारी द्वारा उस वित्त वर्ष के अंत से, जिसमें परियोजना को मंजूरी दी गई थी, से पांच वर्षों की अवधि के भीतर परियोजना को पूरा किया जाएगा ।

(3) निर्धारिती पूर्ववर्ती वर्ष, जिसके लिए वह धारा 35कघ के अधीन कटौती का दावा करने का आशय रखता है, के दौरान सभी पूजी व्ययों के पूर्ण व्यौरे सहित परियोजना की पृथक लेखा बहियां रखेगा और धारा 35कघ के अधीन कर फायदों का लाभ लेने के लिए आय-कर विभाग को सम्यक् तारीख तक सुसंगत आय-कर विवरणियां फाइल करेगा ।

(4) धारा 35कध की उपधारा (8) के खंड (g) के उपखंड (vii) के अधीन अधिसूचित परियोजना का शासन इस नियम के उपबंधों के अधीन उस विस्तार तक होना जारी रहेगा जिस तक ये समय-समय पर संशोधित अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन न करते हों ।

(5) इस नियम में,-

(क) "साध्य गृह इकाईयों" के निम्नलिखित प्रवर्ग होंगे :-

प्रवर्ग	किराया योग्य क्षेत्र (वर्ग मीटर में)	
	विनिर्दिष्ट शहर	अन्य शहर
आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग (इडक्ट्यूएस)	25 वर्ग मीटर तक	30 वर्ग मीटर तक
निम्न आय वर्ग (एलआईजी)	25 से अधिक किंतु 50 तक	30 से अधिक किंतु 60 तक
मध्य आय वर्ग (एमआईजी)	50 से अधिक किंतु 70 तक	60 से अधिक किंतु 85 तक

(ख) "प्रचालनों की तारीख" से वह तारीख अभिप्रेत है जिसको आवास और शहरी ग्रामी उन्मूलन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा विरचित भागीदारी में साध्य गृह स्कीम के अधीन सशक्त सक्षम प्राधिकारी द्वारा परियोजना भंजूर की गई है ;

(ग) "आवास इकाई" से वास करने, पकाने और स्वच्छता आवश्यकताओं के लिए पृथक् सुविधाओं सहित भवन में,- (i) किसी बाहरी दरवाजे से या किसी आंतरिक दरवाजे से या किसी सहगामी मध्य भार्ग से जहां सीधे पहुंचा जा सकता हो किन्तु किसी अन्य गृहस्थ के वासीय स्थान से नहीं, और (ii) सहभाग्य भोजन के क्षेत्र शामिल नहीं हैं, विशेषतावाली पृथक् स्वतंत्र अन्य आवासीय इकाई अभिप्रेत है ;

(घ) "परियोजना" से साध्य गृह परियोजना अभिप्रेत है ;

(ङ) "किराया योग्य क्षेत्र" से किसी फर्श स्तर पर कुल कारपेट क्षेत्र अभिप्रेत है जिसमें भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा विरचित और प्रकाशित भारतीय मानक - भवनों की कुर्सी, कारपेट और किराया योग्य क्षेत्रों का मापमान, आईएस 3861: 2002 के उपबंधों के अनुसार रसोईघर, पेन्ट्री, भंडार, शौचालय, स्नानघर, अनावृद्धित बरामदे का पचास प्रतिशत और आवृद्धित बरामदे का शत प्रतिशत क्षेत्र शामिल है ;

(च) "विनिर्दिष्ट नगरों" से निम्नलिखित अभिप्रेत है -

- (i) बहुत मुंबई शहरी संघट्ट ;
- (ii) दिल्ली शहरी संघट्ट ;
- (iii) कोलकाता शहरी संघट्ट ;
- (iv) चेन्नई शहरी संघट्ट ;
- (v) हैदराबाद शहरी संघट्ट ;
- (vi) बंगलोर शहरी संघट्ट ;
- (vii) अहमदाबाद शहरी संघट्ट ;
- (viii) फरीदाबाद ज़िला ;
- (ix) गुडगांव ज़िला ;
- (x) गोतमबुद्ध नगर ज़िला ;

- (xi) गाजियाबाद जिला ;
- (xii) गांधी नगर जिला ; और
- (xiii) सिकंदराबाद नगर

स्पष्टीकरण.- इस खंड के प्रयोजनों के लिए,-

किसी शहरी संघट्ट से मिलकर बनने वाला क्षेत्र वह क्षेत्र होगा जिसे नवीनतम जनगणना के आधार पर ऐसे शहरी संघट्ट में शामिल किया गया है ;

(छ) "कुल आबंटनीय किरायायोग्य क्षेत्र" से सभी प्रस्तावित गृह इकाइयों या गैर गृह इकाइयों का कुल किराया योग्य क्षेत्र अभिप्रेत है, किन्तु इसमें सामान्य प्रसुविधाओं और सेवाओं के लिए विहित क्षेत्र शामिल नहीं हैं ।"

[अधिसूचना सं. 01/2012/फा. सं. 142/24/2011-एसओ (टीपीएल)]

विमल आनंद, अवर सचिव

प्ररूप सं. ग 3८

[नियम 11-0क(1)(क) देखें]

धारा 35कघ के अधीन विनिर्दिष्ट कारबार के रूप में साध्य गृह परियोजना की अधिसूचना के लिए आवेदन

1.1 विनिर्दिष्ट कारबार का नाम और पता (पूर्ण और स्पष्ट अक्षरों में) :-

1.2 निर्धारिती के ब्यौरे

- (i) नाम (पूर्ण और स्पष्ट अक्षरों में)
- (ii) क्या नाम में कोई परिवर्तन है ? यदि हां, तो पुराना नाम
- (iii) पैन संख्या
- (iv) पूरा पता
- (v) कार्यालय का फोन नं. (एसटीडी सहित)
- (vi) मोबाइल नं. ई-मेल का पता
- (vii) निगमन/प्ररूपण/जन्म की तारीख (दिन / मास / वर्ष)
(जो भी लागू हो)
- (viii) प्राप्तिः

[पल्लिक कंपनी - 1, प्राइवेट कंपनी - 2, साधारण भागीदारी फर्म - 3, स्थानीय प्राधिकरण - 4, सहकारी सोसाइटी - 5, एलएलपी - 6, कोई अन्य एओपी/बीओआई कृत्रिम विधिक व्यक्ति - 7, व्यष्टि - 8, हिन्दू अविभक्त कुटुंब - 9, कोई अन्य व्यक्ति - 10 (कृपया विनिर्दिष्ट करें :)]

(ix) यदि घरेलू कंपनी है तो (सही का निशान लगाएं)

(x) आय-कर वार्ड/वृत्त

(xi) आवासीय प्रास्थिति (सही का निशान लगाएं) निवासी अनिवासी

2.1 प्रस्तावित परियोजना का अवरथान :-

(i) परियोजना का नाम (यदि कोई है).....

(ii) प्रस्तावित परियोजना के अवस्थान का पूरा पता

२२ प्रस्तावित परियोजना के ब्यौरे :-

(i) परियोजना की विभिन्न इकाइयों का किरायायोग्य क्षेत्र (वर्गमीटर में उपदर्शित करें) :-

(ii) संनिर्माण किए जाने वाले अन्य क्षेत्रों के ब्यौरे (सामान्य प्रसुविधाएं आदि) :-

2.4 प्रस्तावित विनिधान (रकम लाख रुपए में)

2.5 परियोजना प्रारंभ होने की संभाव्य या वास्तविक तारीख.....

10 GI/12-2

3.1 क्या निर्धारिती की प्रस्तावित परियोजना के आस-पास कोई भूमि या परियोजना है (यदि हां तो उसके ब्यौरे दें) हां/नहीं

3.2 क्या प्रस्तावित परियोजना पृथक पहचाने जाने वाले क्षेत्र में अवस्थित है या विकसित की जा रही है हां/नहीं

3.3 क्या परियोजना अन्य परियोजनाओं से स्वतंत्र है या किसी अन्य परियोजना का विस्तार या भाग है हां/नहीं

3.4 निर्धारिती के उस भूमि पर जिसपर परियोजना अवस्थित है, स्वामित्व की प्रकृति हां/नहीं

3.5 क्या परियोजना का किसी करार के अधीन विकास किया जा रहा है, यदि हां तो ऐसे करार में अन्य पक्षकारों के (आवेदक से भिन्न) ब्यौरे हां/नहीं

3.6 क्या नियम 11-0क के उपनियम (2) में वर्णित निम्नलिखित प्रत्येक शर्त को पूरा किया गया है :-

i.	परियोजना को आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा विरचित भागीदारी में साध्य गृह स्कीम के अधीन सशक्त सक्षम प्राधिकारी द्वारा पूर्व अनुमोदन प्राप्त है ;	हां/नहीं
ii.	परियोजना के प्रचालनों के प्रारंभ होने की तारीख 1 अप्रैल, 2011 को या उसके पश्चात है ;	हां/नहीं
iii.	परियोजना भूमि के ऐसे टुकड़े पर है जिसका न्यूनतम क्षेत्र एक एकड़ है ;	हां/नहीं
iv.	परियोजना के कुल आबंटनीय किराया योग्य क्षेत्र का कम से कम तीस प्रतिशत आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के प्रवर्ग की साध्य गृह इकाइयों से मिलकर बना है ;	हां/नहीं
v.	परियोजना के कुल आबंटनीय किराया योग्य क्षेत्र का कम से कम तीस प्रतिशत आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के प्रवर्ग और निम्न आय वर्ग की साध्य गृह इकाइयों से मिलकर बना है ;	हां/नहीं
vi.	परियोजना के कुल आबंटनीय किराया योग्य क्षेत्र का कम से कम तीस प्रतिशत आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के प्रवर्ग, निम्न आय वर्ग और मध्य आय वर्ग की साध्य गृह इकाइयों से मिलकर बना है ;	हां/नहीं
vii.	विकसित और निर्मित की जाने वाली परियोजना का विन्यास और विशिष्टियां, जिसमें डिजाइन भी है, का अनुमोदन राज्य या संघ राज्यक्षेत्र की सरकार या उसके अभिहित कार्यपालन अभिकरण द्वारा किया जाएगा ;	हां/नहीं

घोषणा

मैं/हम उस अवधि के दौरान साध्य गृह परियोजना का प्रचालन जारी रखेंगे जिसके दौरान आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 35कध के अधीन फायदे का लाभ उठाया जाना है ।

मैं/हम सत्यापित करते हैं कि पूर्वोक्त कथन मेरी/हमारी ज्ञानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है ।

आवेदक के हस्ताक्षर

(नाम स्पष्ट अक्षरों में)

(हस्ताक्षरकर्ता का पदनाम)

स्थान

तारीख

संलग्नकों की सूची

1.	5.
2.	6.
3.	7.
4.	8.

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)
(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd January, 2012

(INCOME-TAX)

S.O. 5(E).—In exercise of the powers conferred by section 295 read with sub-clause (vii) of clause (c) of sub-section (8) of section 35AD of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Rules, 1962, namely:—

1. (1) These rules may be called the Income-tax (First Amendment) Rules, 2011.
 (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Income-tax Rules, 1962, in Part II, in sub-part F, after rule 11-0, the following rule shall be inserted, namely:—

“Guidelines for notification of affordable housing project as specified business under section 35AD.”

11-0A. (1) The form and manner in respect of notification of an affordable housing project as a specified business under sub-clause (vii) of clause (c) of sub-section (8) of section 35AD of the Act shall be as follows:—

- (a) the applicant shall apply for notification of the project in Form No. 3CN to Member (IT), Central Board of Direct Taxes, Department of Revenue, Ministry of Finance, North Block, New Delhi;

(b) if any defect is noticed in the application in Form No. 3CN or if any relevant document is not attached thereto, a deficiency letter may be served on the applicant;

(c) the applicant shall remove the deficiency within a period of fifteen days from the date of service of the deficiency letter or within such further period which, on an application made in this behalf may be extended;

(d) if the applicant fails to remove the deficiency within the period so allowed, the Board, if satisfied, may pass an order treating the application as invalid;

(e) the Board may, before granting approval, call for such documents or information from the applicant as it may consider necessary and may call for further details or information from the applicant as well as from the income-tax authorities and other Departments or agencies, as it may deem fit;

(f) the Board may issue the notification to be published in the Official Gazette granting approval to the project or for reasons to be recorded in writing, reject the application;

(g) the Board may withdraw the approval if it is satisfied that the assessee has ceased its activities relating to the specified business or its activities are not genuine or are not being carried out in accordance with all or any of the conditions under this rule;

(h) no order treating the application as invalid or rejecting the application or withdrawing the approval or cancellation of the notification, shall be passed without giving an opportunity of being heard to the assessee;

(i) a copy of the order invalidating or rejecting the application or withdrawing the approval shall be communicated to the applicant as well as the Assessing Officer and the Commissioner having jurisdiction over the assessee.

(2) A project shall be considered for notification if it fulfils all of the following conditions, namely:—

(a) the project shall have prior sanction of the competent authority empowered under the Scheme of Affordable Housing in Partnership framed by the Ministry of Housing and Urban Poverty Alleviation, Government of India;

(b) the date of commencement of operations of the project shall be on or after the 1st day of April 2011;

(c) the project shall be on a plot of land which has a minimum area of one acre;

(d) at least thirty per cent. of the total allocable rentable area of the project shall comprise of affordable housing units of EWS category;

(e) at least sixty per cent. of the total allocable rentable area of the project shall comprise of affordable housing units of EWS and LIG categories;

(f) at least ninety per cent. of the total allocable rentable area of the project shall comprise of affordable housing units of EWS, LIG and MIG categories;

(g) the remaining ten per cent. or less of the total allocable rentable area of the project may comprise of other residential or commercial units;

(h) the layout and specifications including design of the project to be developed and built shall be approved by the State or Union territory Government or its designated implementing agency;

(i) the project shall be completed within a period of five years from the end of the financial year in which the project is sanctioned by the competent authority empowered under the Scheme of Affordable Housing in Partnership framed by the Ministry of Housing and Urban Poverty Alleviation, Government of India.

(3) The assessee shall maintain separate book of accounts for the project with complete details of all capital expenditure incurred during the previous year on which it intends to claim the said deduction under section 35AD and shall file the relevant income tax returns by the due date to the Income Tax Department to avail the tax benefit under section 35AD.

(4) A project notified under sub-clause (vii) of clause (c) of sub-section (8) of section 35AD shall continue to be governed by the provisions of this rule to the extent it is not in contravention with the provisions of the Act, as amended from time to time.

(5) In this rule,—

(a) "affordable housing units" shall be of the following categories:-

Category	Rentable Area (in square metres)	
	Specified cities	Other cities
Economically Weaker Section (EWS)	Up to 25	Up to 30
Lower Income Group (LIG)	Greater than 25 and up to 50	Greater than 30 and up to 60
Middle Income Group (MIG)	Greater than 50 and up to 70	Greater than 60 and up to 85

10 GI/12-3

- (b) "date of commencement of operations" means the date on which the project is sanctioned by the competent authority empowered under the Scheme of Affordable Housing in Partnership framed by the Ministry of Housing and Urban Poverty Alleviation, Government of India;
- (c) "housing unit" means an independent residential unit with separate facilities for living, cooking and sanitary requirements, distinctly separated from other residential units within the building – (i) directly accessible from an outer door or through an interior door in a shared hallway and not by walking through another household's living space and (ii) excluding any shared dining areas;
- (d) "project" means an affordable housing project;
- (e) "rentable area" means the carpet area at any floor level, including the carpet area of kitchen, pantry, store, lavatory, bathroom, fifty per cent. of unglazed verandah and hundred per cent. of glazed verandah, in accordance with the provisions of the Indian Standard – Method of Measurement of Plinth, Carpet and rentable Areas of Buildings, IS 3861 : 2002, formulated and published by the Bureau of Indian Standards;
- (f) "specified cities" shall mean the following—
 - (i) Greater Mumbai urban agglomeration;
 - (ii) Delhi urban agglomeration;
 - (iii) Kolkata urban agglomeration;
 - (iv) Chennai urban agglomeration;
 - (v) Hyderabad urban agglomeration;
 - (vi) Bangalore urban agglomeration;
 - (vii) Ahmedabad urban agglomeration;
 - (viii) District of Faridabad;
 - (ix) District of Gurgaon;
 - (x) District of Gautam Budh Nagar;
 - (xi) District of Ghaziabad;
 - (xii) District of Gandhinagar; and
 - (xiii) City of Secunderabad;

Explanation.— For the purposes of this clause,—

the area comprising an urban agglomeration shall be the area included in such urban agglomeration on the basis of the latest census;

- (g) "total allocable rentable area" means the total rentable area of all the proposed housing units or non-housing units but excluding the areas earmarked for common facilities and services."

FORM NO. 3CN
 [See rule 11-0A(1)(a)]

Application for notification of affordable housing project as specified business
under section 35AD

1.1 Name and address of the specified business (in full, block letters):-

1.2 Details of the assessee:-

(i) Name (in full, block letters) _____

(ii) Is there any change in the name? If yes, please furnish the old name _____

(iii) PAN

(iv) Complete address _____

(v) Office Phone Number (with STD code) _____

(vi) Mobile No. _____ Email Address _____

(vii) Date of incorporation/formation/birth (DD/MM/YYYY)

 (whichever applicable)

(viii) Status
 [public company - 1, private company - 2, general partnership firm - 3, local authority - 4, cooperative society - 5, LLP - 6, any other AOP/BOI artificial juridical person - 7, individual - 8, HUF - 9, any other person - 10 (please specify: _____)]

(ix) If a domestic company (Tick)

(x) Income Tax Ward/Circle _____

(xi) Residential Status (Tick) Resident Non-Resident

2.1 Location of the proposed project:-

(i) Name of the project (if any) _____

(ii) Complete address of location of the proposed project:-

2.2 Details of the proposed project:-

(i) Rentable area of various units in the project (indicate in sq. metres):-

(ii) Details of other areas to be constructed (common facilities, etc.):-

2.4 Proposed investment (amount in Rs. lakhs) _____

2.5 Expected or actual date of commencement of the project

3.1 Whether the assessee has any land or project adjacent or in the vicinity of the proposed project? (If yes, details thereof.) Yes/No _____

3.2 Whether the proposed project is located or developed as a separate identifiable area? Yes/No

3.3 Whether the project is independent of other projects or is an extension or part of any other project? Yes/No

3.4 The nature of title the assessee holds on the land on which the project is situated _____

3.5 Whether the project is developed under any agreement and if yes, the details of other parties (other than applicant) to such an agreement?

Yes/No

3.6 Whether each of the following conditions mentioned in sub-rule (2) of rule 11-0A is fulfilled:—

(i)	the project has the prior sanction of the competent authority empowered under the Scheme of Affordable Housing in Partnership framed by the Ministry of Housing and Urban Poverty Alleviation, Government of India;	Yes/No
(ii)	the date of commencement of operations of the project is on or after the 1 st day of April, 2011;	Yes/No
(iii)	the project is on a plot of land which has a minimum area of one acre;	Yes/No
(iv)	at least thirty per cent. of the total allocable rentable area of the project comprises of affordable housing units of EWS category;	Yes/No
(v)	at least sixty per cent. of the total allocable rentable area of the project comprises of affordable housing units of EWS and LIG categories;	Yes/No
(vi)	at least ninety per cent. of the total allocable rentable area of the project comprises of affordable housing units of EWS, LIG and MIG categories;	Yes/No
(vii)	the layout and specifications including design of the project to be developed and built have been approved by the State or Union territory Government or its designated implementing agency.	Yes/No

DECLARATION

I/We hereby undertake to continue to operate the affordable housing project during the period in which the benefits under section 35AD of the Income-tax Act, 1961 are to be availed.

I/We hereby certify that the above statements are true and correct to the best of my/our knowledge and belief.

(Signature of Applicant)

(Name in Block Letters)

(Designation of the Signatory)

Place: _____

Date: _____

List of Enclosures:

1. _____

5. _____

2. _____

6. _____

3. _____

7. _____

4. _____

8. _____